seed money for resurvey of lands in the State; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The Government of Andhra Pradesh have submitted a note on re-surveying the entire State in a period of 10 years with an estimated cost of Rs. 12.00 crores per annum or Rs. 120.00 crores for the entire period. In the note, it has been stated that in such a gigantic task liberal assistance from Government of India is absolutely necessary.

भूमिगत जल का संकट

2104. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1992 के "फायनेंसियल एक्सप्रेस" "फेसिंग ग्राऊन्डवाटर क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में भूमिगत जल का स्तर लगातार गिर रहा है और लगभग 54,310 गांवों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार देश में जल के इस बढ़ते हुये संकट का सामना करने के लिये किसी योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भू-जल स्तर में लम्बे समय तक गिरावट की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है **(नीचे देखिए)**। राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा तमिल नाडु राज्यों के कुछेक क्षेत्रों में मई तथा नवम्बर, 1991 के बीच भू-जल स्तर में मौसमी कमी देखी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से जल स्तर में लगातार हो रही गिरावट की स्थिति का पता नहीं चलता है। यह देखा गया है कि जिस वर्ष अच्छी वर्षा होती है, भू-जल का स्तर उठ जाता है। तथापि, गुजरात के मेहसाणा क्षेत्र, जहां पर कृत्रिम भू-जल सम्पूर्ति से संबंधित प्रायोगिक अध्ययन किये गये थे, में भू-जल स्तरों में लगातार गिरावट पाई गई है।

(घ) और (ङ) फरवरी, 1992 में सरकार ने निम्नलिखित स्थानों में भू-जल की कृत्रिम रूप से सम्पूर्ति के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई 367 लाख रुपये की लागत वाली एक योजना अनुमोदित की है :—

(1) कोलार जिला, कर्नाटक के गौरीबिदुर तथा मुलबंगल तालुक।

(2) महाराष्ट्र के अमरावती और जलगांव जिलों में संतरे तथा केले की पैदावार वाले क्षेत्र।

(3) केन्द्र शासित क्षेत्र, दिल्ली।

(4) केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़।

विवरण

देश में मानसून पूर्व अवधि के दौरान भू-जल स्तरों में दीर्घकालीन गिरावट

राज्य	वे जिले जिनके कुछ भागों अथवा क्षेत्रों में भू-जल स्तर में 2 मीटर से अधिक की गिरावट आई है।
आन्ध्र प्रदेश	चित्तूर, कुडुपा, कुरनूल, महबूब नगर, निलौर, रंगारेड्डी
असम	गोपालपाड़ा, जोरहाट, नागौन, उत्तरी लखीमपुर
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भडौच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, राजकोट, साबरकंठा, सूरत सुरेन्द्रनगर ।
हरियाणा	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्दरगढ़ रोहतक।
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, सिरमौर
जम्मू व कश्मीर	जम्मू
कर्नाटक	बंगलौर, बेलगांव, बिल्लारी, बिदर, बिजापुर, चित्रदुर्ग, धारवाड, गुलबर्गा, मांडया, मैसूर, रायचूर, दक्षिणकनारा, तुमकुर
केरल	इडुक्की, कोट्टायम, पट्टनममिठा,
मध्य प्रदेश	बेतूल, भोपाल, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, देवास, धार, गुना, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, मांडला, नरसिंहपुर, रायपुर, राजनंदगांव, सागर, सिग्रोनी, शिवपुरी
महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीद, जलगांव, नासिक, परभनी, सतारा, शोलापुर, सिंहदुर्ग
उड़ीसा	कटक, कोरापुट, कुलबनी
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाडमेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर चुरू, डुंगरपर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनूं, जौधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, टोंक, उदयपुर।

राज्य	वे जिले जिनके कुछ भागों अथवा क्षेत्रों में भू-जल स्तर में 2 मीटर से अधिक की गिरावट आई है।
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बांदा, बुलन्दशहर, देवरिया, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, नैनीताल, रायबरेली, सीतापुर
पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी।
दिल्ली	शहरी खंड, महरौली खंड, अलीपुर खंड

जवाहर रोजगार योजना के अधीन व्यय की गयी धनराशि

2105 **श्रीमति सुषमा स्वराज :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जवाहर रोजगार योजना 1988 में शुरु की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान किस-किस राज्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी; और

(घ) कितने व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) नहीं। देश में जवाहर रोजगार योजना 1.4.89 को शुरू की गई थी।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा समय-समय पर राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी सचिवों के साथ बैठकों में की जा रही है। कार्यक्रम की गुणात्मक समीक्षा के लिए जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन भी शुरू किया गया है। देश में यह कार्य कई अनुसंधान संस्थाओं की मार्फत कराया जा रहा है। समवर्ती मूल्यांकन के परिणामों का पहला सैट जून, 1992 तक उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जवाहर रोजगार योजना के तहत निधियों के राज्यवार उपयोग और इसके कार्यान्वयन के गत तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है।

[देखिए परिशिष्ट 163, अनुपत्र संख्या 41]

Pucca roads for villages

2106. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of State-wise villages which are still not connected with Kutcha road and pucca road;

(b) whether any plan has been drawn to provide these villages with road and connecting roads; and